Volume: 1 Issue: 1 Pages: 10-12

International Journal of Research in Academic World

E-ISSN: 2583-1615

Received: 23/August/2021 Int. J Res. Acad. World, 2021; 1(1):10-12 Accepted: 04/September/2021

विस्तारवाद के विरुद्ध भारत की कठोर नीति

*[1]Kiran Kaur

*[1]Research Scholar Shri Ramadevi Kanya Mahavidhyalaya Rajasthan India.

सारांश

चीन कि विस्तारवादी नीति को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार कई मोर्चो पर तैयारीं कर रही है कूटनीति के साथ साथ विदेशनीति में बदलाव और सेन्ये आधुनिकीकरण तो कर ही रही है साथ ही आत्म निर्भरता पर जोर दिया जा रहा है ! भविष्य में चीन से आयात की संभावनाओं को नजरअंदाज़ करते हुए देश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया जा रहा है ! विदेशनीति के सन्दर्भ में भारत को चीन द्वारा शोषित देशो के समर्थन की आवश्यकता को तलाशते हुए मित्रता का हाथ बढ़ाने की जरुरत है !

Keywords: भारत चीन विवाद, विएतनाम चीन विवाद, एक देश- दो सिद्धांत, कूटनीतिक सम्बन्ध, भारतीय सेना, गलवान घाटी, लद्दाख

प्रस्तावना

"विस्तारवाद" का अर्थ विस्तारवाद शब्द सुनते ही चीन या ड्रैगन का चित्र मस्तिष्क में उभर आता है, आज सिर्फ भारत ही नहीं विएतनामए हांगकांगए ताइवानए तिब्बत भी परेशान हैंए चीन कि विस्तारवादी नीति सेश् ! आज भारत कई गंभीर समस्याओ से गुजर रहा है कई मोर्चों पर लड़ी जाने वाली लड़ाई भारत के लिए बडी चुनौती नहीं है बल्कि एक अवसर है पूरी दुनिया को यह एहसास कराने का कि "भारत कभी अपनी संप्रुभता और अखंडता से समझोता नहीं करेगा"

एक तरफ जहा कोरोना जैसी महामारी से हमारे कोरोना वारियर्स सफ़ेद वर्दी पहन कर इस बीमारी से युद्ध करने में जुटें हैं वही दूसरी तरफ हमारी सीमाओ पर तैनात हमारे जवान मोर्चे को संभाले बेठे हैं ! दोहरे मोर्चे पर देश एकजुट खड़ा दिखाई देता है चाहे कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो या उसी कोरोना के जनक कहे जाने वाले चीन के खिलाफ लड़ाई हो ! चीन की विस्तारवाद की पुराणी आदत रही है, चीन को अगर विस्तारवाद का जनक कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी !चीन द्वारा सीमाओं पर विवाद करने क़ी और फिर उस विवादित क्षेत्र को अपना बताने की आदत वर्षो पुरानी है ! आज पूरी दुनिया चाइना के कारनामो से तंग आ चुकी है! चाहे वो वियतनाम हो, हांगकांग हो, तिब्बत हो, फिलीपींस हो या भारत !

चीन कि इसी विस्तारवादी नीति का परिणाम है कि भारत वर्ष 1962 में अपनी मातृभूमि का 30,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा गँवा चुका है ! चीन की विस्तारवादी नीति ने तिब्बत जेसे स्वतंत्र मुल्क को भी अपने क्षेत्र में विलीन कर अपना राज्य घोषित कर रखा है

1. कूटनीतिक स्तर पर चीन की घेराबंदी

हम जानते हैं हर स्तर पर चीन, भारत के लिए अवरोध का कार्य करता आया है वो चाहे सीमाओ पर हो, UNO में मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकी को blacklist करने कि बात हो अथवा संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की वीटो पावर देश बनाने की बात हो ! वैसे तो भारत वसुधैव कुटुम्बकम के सिधांत पर कार्य करने वाला देश है परन्तु विश्व का कोई भी देश भारत कि एकता, अखंडता और संप्रभुता पर चोट करता है भारत को अपनी रणनीति में बदलाव करना बेहद आवश्यक हो जाता है जिसके निम्न पहलु देश को और अधिक समृद्ध बना सकते है

- जो देश आज चाइना के खिलाफ आन्दोलन कर रहे है जिनमें विएतनाम, ताइवान, होंम्ग कोंग, तिब्बत, शिन्जेयाम्ग प्रान्त, जापान, अमेरिका आदि आते हैं, को साथ लेकर चलने कि जरुरत है आज उन देशो का साथ देने कि सख्त जरुरत है जो चीन की क्रूर विस्तारवादी नीति का शिकार हो रहे हैं.
- ताइवान आज अकेला One China Policy (एक देशए दो सिद्धांत) के खिलाफ मजबूती से खड़ा हुआ है भारत को चाहिये कि ताइवान को उसके हकों के लिए सहायता प्रदान करने में मदद की जाये !
- ताइवान की राष्ट्रपति "शाई इंग-वेन" ने अपने दुसरे कार्यकाल में चीन की आलोचना करते हुए साफ़ कर दिया

*Corresponding Author: Shashi K Agarwal

कि ताइवान एक देश दो व्यवस्था के सिद्धांत पर कार्य नहीं करेगा

"लोकतान्त्रिक ताइवान चीन के नियम- कायदे कभी कबूलण्नहीं करेगा और चीन को इस हकीकत के साथ शांति से जीने का तरीका खोजना होगा"

शाई इंग-वेन

(राष्ट्रपति ताइवान)

फोटो 1: (Taiwan Times की 16 जुलाई 2020 की अखबारों में छपी खबर के साथ ये फोटो जिसमे भगवन राम को अपने धनुष से ड्रैगन का वध करते हुए दिखाया गया है) [1]

- हाल ही में होन्ग कोंग में हुए बड़े स्तर पर अपने वर्चस्व को बचाने के आन्दोलन को प्रोत्साहित करने कि जरुरत है ! होन्ग कोंग के मुद्दे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचो से आवाज़ उठाने में और सोशल मीडिया पर प्रचारित करने कि जरुरत है !
- तिब्बत चाइना का राज्य नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र देश है लेकिन अपनी आजादी के लिए तिब्बत के लोगो को संघर्ष करना पड़ रहा है, भारत को तिब्बत के हितो के लिए कार्य करना चाहिए ! [2]
- दलाई लामा और उनके अनुयांयिओ को दिल्ली बुलाना चाहिए और चाइनीज Embassy के आगे उन्हे प्रदर्शन करने कि आनुमति मिलनी चाहिए और उसका प्रसारण यू tube व् अन्य माध्यमो से पूरी दुनिया तक पहुचाया जाये.

फोटो 2 & 3: (तिब्बत के लोगो का चीन के खिलाफ प्रदर्शन source- **गूगल)**

- चीन की विस्तारवादी नीति के चलते विएतनाम से भी चीन का विवाद चल रहा है ! दोनों देशो के मध्य "विएतनाम चीन विवाद 1979" में भी हो चूका है
- विएतनाम कई वर्षो से भारत से मिसाइल प्रणाली की मांग कर रहा है आज विएतनाम को सहायता करने की जरुरत है हमारे सभी पड़ोसी मुल्को के पास हमारी मिसाइल प्रणाली की सभी मिसाइले (अग्नि, त्रिशूल, ब्रह्मोस, नाग,)कि आपूर्ति करने की जरुरत है ! ताकि वक़्त पर आने पर हम चीन को घेर सके!
- चीन के शिम्जेयांग प्रान्त में हो रहे "उइगर मुस्लिमो" पर अत्याचारों के खिलाफ भारत को आवाज उठानी चाहिए और इस मुद्दे को UNO तक लाने के प्रयास करने की जरुरत है !

2. सैन्य स्तर पर चीन की घेराबंदी

हाल ही में लद्दाख में 14 व 15 जून 2020 कि रात को हुई भारतीय सेना और चाइना कि PLA (Peoples liberation Army) के मध्य झड़प में चाइना को मुह की खाने के बाद यह मान लेना कि चाइना पीछे हट जायेगा[3] एक कल्पना मात्र ही है वो आज गलवान से गया है फिर अरुणाचल में आँख दिखायेग, सिक्किम से आएगा,लाहौल स्पीति में विवाद खड़ा करेगा इसलिए चीन के स्थायी समाधन के लिए कूट नीतिक

स्तर के अलावा सेन्य स्तर पर भी अपनी रणनीति में बदलाव करने कि जरुरत है !

- टूर ऑफ़ ड्यूटी का आध्यादेश (Tour of Duty) जल्द से जल्द लाकर हम हमारी सेना कि क्षमता को कई गुना समृद्ध कर सकते
- Son of Soil (मिटटी के बेटे) के सिधांत को बढ़ावा देने कि जरुरत हैं LAC (वास्तविक नियंत्रण रेखा) से लगने वाले सभी सीमावर्ती राज्यों में स्थानीय लोगो को सेना में शामिल किया जाये ताकि वे लोग अपनी असाधारण क्षमता से उन इलाको कि भी सुरक्षा कर सके जहा प्रतिकूल पारिस्थितियो के वे योग्य है उनका जनम ही ऊंचाई पर हुआ है !
- सभी **NCC** केडेट्स (सिक्किमं स्काउट्स, मणिपुर स्काउट्स, आसाम स्काउट्स आदि) की टुकडियो को जो सीमावर्ती क्षेत्र में हैं उन्हें Infantry या Regiments में बदला जाये और संख्या में भी इजाफा किया जाये !
- इजरायल, रूस, अमेरिका, जापान जेसे ताकतवर देशो के साथ युद्ध अभ्यास किये जाये और अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया जाये ताकि भारत को एशिया में उसका मजबूत प्रतिद्वंदी होने का एहसास कराया जा सके!

भारतीय प्रधानमंत्री का LAC की अग्रिम चोकियो पर जाकर चाइना को साफ़ सन्देश देना भी इस बात पर बल देता है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है

“लेह लद्दाख से लेकर कारगिल और सियाचीन तक रेजांगला की बर्फीली चोटियों से लेकर गलवान घाटी के ठन्डे पानी की धारा तक हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा – जर्रा, हर कंकड़, पत्थर भारतीय सैनिको के पराक्रम की गवाही देते है”

प्रधानमंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी)

3. व्यापारिक नीति में बदलाव

भारत और चीन के मध्य 100 बिलियन डोलर का ट्रैड है जिसे सम्पूर्ण रूप से समाप्त कर पाना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नही है जिसके लिए भारत सरकार ने कई अहम कदम भी उठाये है -

- FDI नीति में बदलाव लाकर भारत सरकार ने चीन की कंपनियों को बड़ा झटका दिया है अब चीन को भारत कि किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी अब तक यह नियम केवल बंगलदेश और पाकिस्तान कि कंपनियों पर ही लागू होता था भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा मानते हुए चीन के 59(Chinese Apps tiktok व अन्य) एंड्राइड Applications को बैन कर दिया है जिसमे आमजन का भी सहयोग इस बात को दर्शाता है कि देश और उसकी सुरक्षा सर्वोपरी है
- बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) और अन्य सरकारी कंपनियों में चीन के 50 उपकरणों के उपयोग पर सरकार ने पाबन्दी लगा दी है जो चीन को व्यापारिक स्तर पर एक आघात पहुचाने में कारगर सिद्ध होगा

4. नागरिको की सहभागिता

आज हर कोई हक़ कि बात करता है लेकिन कर्त्तव्य की बात कोइ नहीं करता एक नागरिक होने के नाते आज हमें भी जापानीज लोगो कि तरह अपने देश के लिए विदेशी सामानों को त्यागने की जरुरत है ! 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किये गए परमाणु बम हमले के बाद से वहां के जापानीज नागरिको ने अमेरिकी वस्तुओ का उपयोग और उपभोग करना बंद कर दिया उसके नतीजे हे कि आज अमेरिका अपनी एक सुई भी नहीं बेच सकता जापान में! आत्मनिर्भर भारत मिशन की सफलता के लिए हमें विदेशी उत्पादों के स्थान पर देशी उत्पादों के उपयोग की सम्भावनाये तलाशने की जरुरत है ! हम जानते हैं कि आज चीनी सामान हमारे घरो मे भी मोजूद ह

सन्दर्भ सूची

1. आजतक न्यूज़ चैनल, 15 जून, 2020
2. Taiwan टाइम्स 16 जून 2020
3. BBC Hindi News Channel
4. VOA News
5. विकिपीडिया